गुरुवार, 18 जून, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

मेसी ने रचा नया इतिहास, 200वें अंतरराष्ट्रीय मैच में अर्जेंटीना को दिलाई शानदार जीत

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

अल्फ़ा में रितिक रोशन की झलक फैन्स उत्साहित

Page-05

जी-7 समिट में हॉट-माइक खोले नेताओं के अनौपचारिक राज

दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों के संगठन जी-7 की बैठकें आमतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और भू-राजनीतिक संकटों पर गंभीर चर्चाओं के लिए जानी जाती हैं। लेकिन फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ ऐसे पल भी सामने आए जिन्होंने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। इसकी वजह बने 'हॉट माइक्रोफोन', जिन्होंने नेताओं के अनौपचारिक संवाद रिकॉर्ड कर लिए।बैठक के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई नेताओं के बीच हुई हल्की-फुल्की बातचीत रिकॉर्ड हो गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मेलोनी ने धूम्रपान छोड़ने के अपने अनुभव साझा किए, जबकि मैक्रों अपनी घड़ी खो जाने की घटना का जिक्र करते दिखाई दिए।सबसे अधिक चर्चा ट्रंप की टिप्पणियों को लेकर हुई। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कई विषयों पर टिप्पणी की, जिस पर मौजूद नेताओं के बीच हंसी-मजाक का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर इन वीडियो क्लिप्स को लाखों बार देखा गया और लोगों ने नेताओं के इस मानवीय पक्ष पर दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दीं।विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे अनौपचारिक क्षण अक्सर तनावपूर्ण माहौल को सहज बनाने में मदद करते हैं। हालांकि आधिकारिक बैठकों में चर्चा के विषय गंभीर होते हैं, लेकिन नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर संवाद कई बार महत्वपूर्ण निर्णयों को आसान बना देता है।इस बार भी जी-7 सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, पश्चिम एशिया संकट, यूक्रेन युद्ध और आर्थिक सहयोग जैसे गंभीर मुद्दे एजेंडे में रहे। बावजूद इसके, हॉट-माइक से सामने आए ये दृश्य सम्मेलन के सबसे चर्चित क्षणों में शामिल हो गए। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि विश्व राजनीति के बड़े चेहरे भी औपचारिक मंचों से इतर सामान्य मानवीय बातचीत करते हैं।

शिवसेना का बगावतों भरा इतिहास: चार बड़े विद्रोह जिन्होंने बदल दी महाराष्ट्र की राजनीति

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का इतिहास केवल चुनावी सफलताओं और सत्ता की साझेदारी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह बड़े राजनीतिक विद्रोहों और संगठनात्मक संघर्षों का भी गवाह रहा है। एक बार फिर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) में संभावित टूट की चर्चाओं के बीच पार्टी के इतिहास की पुरानी बगावतें चर्चा में आ गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवसेना के भीतर समय-समय पर हुए विद्रोहों ने न केवल पार्टी की दिशा बदली, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति को भी नए सिरे से परिभाषित किया।शिवसेना की स्थापना 1966 में बालासाहेब ठाकरे ने की थी। शुरुआती दशकों में संगठन पूरी तरह ठाकरे परिवार के प्रभाव में रहा, लेकिन समय के साथ नेतृत्व और रणनीति को लेकर असंतोष भी उभरता रहा। पहली बड़ी बगावत 1991 में देखने को मिली, जब छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उस समय इसे बाल ठाकरे के नेतृत्व के लिए बड़ा झटका माना गया था।इसके बाद 2005 में नारायण राणे ने पार्टी से अलग होकर नया राजनीतिक रास्ता चुना। राणे उस समय शिवसेना के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उनके जाने से संगठन को बड़ा नुकसान हुआ और कोंकण क्षेत्र में पार्टी की पकड़ प्रभावित हुई।तीसरा बड़ा झटका 2022 में लगा, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने बगावत कर दी। इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया और राज्य की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया। बाद में चुनाव आयोग ने भी शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी।राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवसेना का इतिहास बताता है कि संगठन के भीतर नेतृत्व संघर्ष और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में यदि फिर कोई बड़ा विभाजन होता है तो उसका असर केवल पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीतिक संरचना प्रभावित हो सकती है।फिलहाल सभी निगाहें उन सांसदों की गतिविधियों पर टिकी हैं, जिनके नाम संभावित बागियों के रूप में लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही यह तय होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में वास्तव में कोई नया भूचाल आने वाला है या नहीं।

आरोपियों की रिहाई पर हुआ स्वागत माला पहनाने का वीडियो वायरल

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बने अभिजीत दिपके थप्पड़ कांड ने नया मोड़ ले लिया है। दिपके पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो युवकों की रिहाई के बाद उनका सार्वजनिक स्वागत किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में समर्थकों को आरोपियों को माला पहनाते, नारेबाजी करते और उनका अभिनंदन करते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई है कि क्या कानून अपने हाथ में लेने वालों का इस तरह सम्मान किया जाना उचित है।घटना की शुरुआत उस समय हुई थी जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके जयपुर में एक विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान कथित रूप से दो व्यक्तियों ने उनके साथ हाथापाई की और थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।हालांकि बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक एकत्र हुए। वायरल वीडियो में आरोपियों को फूल-मालाएं पहनाई जाती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'भारत माता की जय' जैसे नारे भी लगाए गए। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन हिंसा या शारीरिक हमले को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने भी आरोपियों के सार्वजनिक सम्मान पर आपत्ति जताई है।

अमेरिकी वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़ा एक नया विवाद सामने आ गया है। अमेरिकी पैसिफिक कमांड की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत का ऐसा नक्शा प्रदर्शित होने का मामला सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भारत के बजाय पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया बताया जा रहा है।मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज हो गई। भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न अंग हैं तथा पीओके भी भारत का ही हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में अमेरिकी वेबसाइट पर कथित रूप से गलत नक्शा दिखाया जाना संवेदनशील विषय माना जा रहा है।विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के दौर में इस प्रकार की त्रुटियां अनावश्यक विवाद पैदा कर सकती हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने क्वाड, इंडो-पैसिफिक रणनीति और रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ऐसे में नक्शे से जुड़ा कोई भी विवाद राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लेता है।विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस तरह के मामलों को केवल तकनीकी गलती मानकर नजरअंदाज नहीं करता। अतीत में भी भारत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और कंपनियों के समक्ष गलत नक्शों पर आपत्ति दर्ज कराता रहा है।अब निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिकी प्रशासन इस मामले पर क्या स्पष्टीकरण देता है। यदि यह तकनीकी त्रुटि है तो उसके सुधार की उम्मीद की जा रही है। वहीं भारत की ओर से भी आधिकारिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यह प्रकरण एक बार फिर दिखाता है कि मानचित्र और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दे भारत की विदेश नीति में अत्यंत संवेदनशील बने हुए हैं।

जब भारत ने अमेरिका को दिया कड़ा जवाब 2013 का देवयानी खोबरागड़े प्रकरण फिर चर्चा में

भारत और अमेरिका आज भले ही रणनीतिक साझेदार माने जाते हों, लेकिन दोनों देशों के संबंधों में ऐसे दौर भी आए हैं जब कूटनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया था। दिसंबर 2013 का देवयानी खोबरागड़े प्रकरण ऐसा ही एक मामला था, जिसने दोनों देशों के रिश्तों में असहजता पैदा कर दी थी। अब 2026 में भारतीय नाविकों की मौत और समुद्री सुरक्षा को लेकर उठी बहस के बीच उस घटना की चर्चा फिर होने लगी है।दिसंबर 2013 में न्यूयॉर्क में भारत की तत्कालीन उप महावाणिज्यदूत देवयानी खोबरागड़े को अमेरिकी अधिकारियों ने वीजा धोखाधड़ी और घरेलू सहायिका के वेतन संबंधी आरोपों में गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय पक्ष का आरोप था कि गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें सार्वजनिक रूप से हिरासत में लिया गया और सामान्य अपराधियों की तरह तलाशी भी ली गई।इस घटना ने भारत में व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा कर दी थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास को मिली कई विशेष सुविधाएं वापस ले ली गईं। अमेरिकी राजनयिकों के पहचान पत्रों और विशेषाधिकारों की भी समीक्षा की गई। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर विरोध देखने को मिला।भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह अपने राजनयिकों के सम्मान और संप्रभु अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। बढ़ते दबाव के बाद अमेरिका को भी स्थिति संभालने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने पड़े। अंततः देवयानी खोबरागड़े को संयुक्त राष्ट्र मिशन में स्थानांतरित किया गया, जिससे उन्हें अतिरिक्त राजनयिक संरक्षण प्राप्त हो गया।विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना भारत की बदलती वैश्विक स्थिति का प्रतीक थी। पहली बार भारत ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सामने खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और अपने राजनयिक सम्मान के मुद्दे पर पीछे हटने से इनकार कर दिया। आज जब भारतीय नाविकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर चर्चा हो रही है, तब यह प्रकरण फिर याद दिला रहा है कि वैश्विक मंच पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दृढ़ कूटनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है।

हिन्दी जगत महामंच
www.tvbharatvarsh.in
भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर
प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

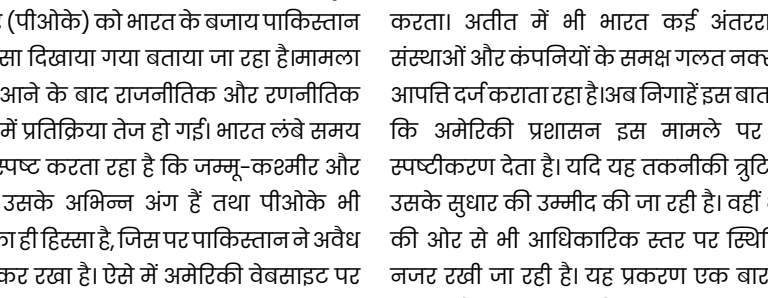

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2 - 3)	फुल पेज (कवर 4 - अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

जी-7 शिखर सम्मेलन में ईरान समझौता बना सबसे बड़ा मुद्दा

पश्चिम एशिया में स्थिरता की नई उम्मीद

विश्लेषकों का मानना है कि इस समझौते से तेल बाजार में अनिश्चितता कम हो सकती है। पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा था। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की नजर भी इस घटनाक्रम पर बनी हुई है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

कनाडा में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान और पश्चिमी देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते ने वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। सम्मेलन में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया। सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य में क्षेत्रीय स्थिरता, परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।हाल के महीनों में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रतिबंधों को लेकर तनाव बना हुआ था। ऐसे माहौल में हुए अंतरिम समझौते को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते का समर्थन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करना और संभावित सैन्य टकराव की आशंकाओं को कम करना है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समझौते की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।सम्मेलन में यूरोपीय देशों ने भी समझौते का स्वागत किया और इसे संवाद आधारित समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी अस्थिरता का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ता रहा है। ऐसे में किसी भी प्रकार की कूटनीतिक प्रगति का अंतरराष्ट्रीय महत्व है।विश्लेषकों का मानना है कि इस समझौते से तेल बाजार में अनिश्चितता कम हो सकती है। पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा था। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की नजर भी इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। भारत सहित कई देशों ने स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए संवाद की प्रक्रिया जारी रखने की आवश्यकता बताई है।हालांकि समझौते को लेकर आलोचनाएं भी सामने आई हैं। कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते के दीर्घकालिक परिणामों का आकलन अभी जल्दबाजी होगा। इजरायल सहित कुछ देशों ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को प्रमुखता से उठाया है और समझौते के क्रियान्वयन पर करीबी नजर रखने की बात कही है।फिलहाल जी-7 सम्मेलन से निकला संदेश यह है कि प्रमुख वैश्विक शक्तियां पश्चिम एशिया में किसी नए सैन्य संघर्ष के बजाय कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देना चाहती हैं। आने वाले महीनों में समझौते के प्रभाव और उसके पालन की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।

नॉन-लिस्टेड पब्लिक शेयरहोल्डिंग वाली कंपनियों में निवेश करने में बहुत ज्यादा रिस्क

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार निवेशकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपके पैसे डूबने से बचा सकती है। सेबी ने बुधवार को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट के जरिए नॉन-लिस्टेड पब्लिक शेयरहोल्डिंग वाली कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर निवेशकों के लिए चेतावनी जारी की है। सेबी ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म न तो मान्यता प्राप्त हैं और न ही नियामक के अधीन आते हैं। बाजार नियामक सेबी ने बताया कि उसे कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी मिली है जो नॉन-लिस्टेड पब्लिक शेयरहोल्डिंग वाली कंपनियों की सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रहे हैं और इससे निवेशकों को बड़ा जोखिम हो सकता है। सेबी ने बयान में दिसंबर, 2024 और अगस्त, 2016 में जारी अपनी पुरानी चेतावनियों को दोहराते हुए कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लेनदेन करना या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है। मार्केट रेगुलेटर ने ये भी बताया कि उसने पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फैंटेसी गेम्स और नॉन-लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को लेकर आगाह किया है। सेबी ने कहा, " निवेशकों को एक बार फिर आगाह किया जाता है कि वे ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर लेनदेन या 'ट्रेडिंग' न करें और न ही अपनी निजी जानकारी साझा करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स सेबी द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त नहीं हैं।"

ईरान समझौते के बाद इजरायल की राजनीति में उबाल नेतन्याहू पर बढ़ा दबाव

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

ईरान और पश्चिमी देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद इजरायल की घरेलू राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर विपक्ष ने तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि समझौता इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह संबोधित नहीं करता। इसके साथ ही देश के भीतर सुरक्षा, विदेश नीति और क्षेत्रीय रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है।विपक्षी दलों का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर इजरायल लंबे समय से कड़ा रुख अपनाता रहा है। ऐसे में अंतरिम समझौते के बाद सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। कई विपक्षी नेताओं ने संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की है।दूसरी ओर नेतन्याहू सरकार का कहना है कि वह समझौते के प्रत्येक पहलू पर करीबी नजर रखे हुए है। सरकार के अनुसार, इजरायल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां मौजूद हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू राजनीति पर भी असर डाल सकता है। हाल के वर्षों में सुरक्षा संबंधी मुद्दे इजरायल की चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में ईरान समझौते को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की रणनीति पर जनता की नजर बनी हुई है।विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समझौते का प्रभाव सकारात्मक रहता है और क्षेत्रीय तनाव में कमी आती है तो यह पूरे पश्चिम एशिया के लिए लाभकारी हो सकता है। वहीं किसी भी प्रकार की असहमति या उल्लंघन की स्थिति में राजनीतिक विवाद और सुरक्षा चिंताएं फिर से बढ़ सकती हैं। फिलहाल इजरायल में यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का प्रमुख विषय बना हुआ है।

ईरान समझौते में 300 अरब डॉलर निवेश कोष की चर्चा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

ईरान और पश्चिमी देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद अब एक प्रस्तावित 300 अरब डॉलर के निवेश कोष को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। समझौते से जुड़े दस्तावेजों और राजनयिक सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, यह कोष ईरान की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण, ऊर्जा क्षेत्र के विकास, आधारभूत ढांचे के विस्तार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों और ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना पूरी तरह लागू होती है तो पश्चिम एशिया की आर्थिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्षों से प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनाव का सामना कर रहे ईरान को अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। इससे ऊर्जा उत्पादन, परिवहन नेटवर्क, बंदरगाहों और विनिर्माण क्षेत्र में नई परियोजनाओं का रास्ता खुल सकता है।अमेरिका और यूरोपीय देशों के कुछ अधिकारियों का मानना है कि आर्थिक सहयोग राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने का माध्यम बन सकता है। समर्थकों का तर्क है कि निवेश और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि से क्षेत्रीय तनाव कम करने में मदद मिलेगी। वहीं आलोचकों का कहना है कि किसी भी बड़े आर्थिक पैकेज के साथ निगरानी और पारदर्शिता की मजबूत व्यवस्था आवश्यक होगी, ताकि धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही हो सके। ऊर्जा बाजार से जुड़े जानकारों के अनुसार, ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को मजबूती मिल सकती है। इससे लंबे समय में तेल की कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत, चीन और यूरोप के कई देशों की कंपनियां संभावित निवेश अवसरों पर नजर बनाए हुए हैं।

यूक्रेन को लेकर जी-7 का साझा संदेश

रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर सहमति

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

जी-7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध एक बार फिर प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा। सदस्य देशों के नेताओं ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन को दोहराते हुए रूस पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाए रखने की रणनीति पर सहमति व्यक्त की। सम्मेलन के दौरान जारी बयान में कहा गया कि युद्ध का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानूनों और यूक्रेन की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए होना चाहिए।बैठक में यूक्रेन को आर्थिक सहायता, सैन्य सहयोग और पुनर्निर्माण योजनाओं पर भी चर्चा हुई। कई देशों ने युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता बढ़ाने का आश्वासन दिया। नेताओं का मानना है कि लंबे समय से जारी संघर्ष ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित किया है।जी-7 देशों ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की प्रभावशीलता की समीक्षा भी की। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को सीमित करना और उसे बातचीत की दिशा में प्रेरित करना है। यूरोपीय देशों ने कहा कि संघर्ष समाप्त होने तक यूक्रेन को समर्थन जारी रखा जाएगा।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह रहा कि पश्चिमी देशों के बीच यूक्रेन को लेकर अब भी व्यापक सहमति बनी हुई है। हालांकि युद्ध के लंबा खिंचने से आर्थिक लागत बढ़ रही है, फिर भी अधिकांश सदस्य देश अपने रुख में बदलाव के पक्ष में नहीं दिखे। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में युद्ध की दिशा और संभावित शांति वार्ताओं की संभावनाएं वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती रहेंगी। फिलहाल जी-7 देशों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यूक्रेन का मुद्दा उनकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में बना रहेगा।

संपादक की कलम से

युवाओं का भविष्य और व्यवस्था की जिम्मेदारीदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और रोजगार के मुद्दे एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में हैं। हाल के वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती में देरी और चयन प्रक्रियाओं से जुड़े विवादों ने लाखों युवाओं की उम्मीदों को प्रभावित किया है। यही कारण है कि जब भी यह मुद्दा उठता है, उसे व्यापक जनसमर्थन और राजनीतिक महत्व दोनों प्राप्त होते हैं।भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। यह स्थिति हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार क्षमता देश के विकास को नई गति दे सकती है। चुनौती इसलिए कि यदि उन्हें समय पर शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर नहीं मिले तो निराशा और असंतोष बढ़ सकता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि उसके युवा अपने भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं।पेपर लीक की घटनाएं केवल एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा देती हैं। वर्षों तक कठिन परिश्रम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा रद्द होना या परिणामों पर विवाद खड़ा होना मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बड़ी क्षति है। यह केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास से जुड़ा विषय है। इसलिए ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई, दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और पारदर्शी जांच आवश्यक है।सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। डिजिटल निगरानी, कड़े कानून और परीक्षा प्रबंधन में सुधार जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इन उपायों का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और समयबद्ध व्यवस्था का अनुभव होगा। दूसरी ओर विपक्ष का दायित्व केवल आलोचना करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देकर समाधान की दिशा में योगदान देना भी है।आज आवश्यकता इस बात की है कि रोजगार, शिक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाए। युवाओं का विश्वास किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है। यदि यह विश्वास मजबूत रहेगा तो देश की विकास यात्रा भी मजबूत होगी। इसलिए सरकार, राजनीतिक दलों और संस्थाओं को मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें प्रतिभा को अवसर मिले और परिश्रम का सम्मान सुनिश्चित हो सके।युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है।

कोटा से राहुल गांधी ने छेड़ी युवाओं की लड़ाई पेपर लीक और बेरोजगारी को बनाया बड़ा मुद्दा

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कई भर्ती परीक्षाएं या तो रद्द हुई या फिर विवादों में घिर गईं, जिससे लाखों युवाओं का समय और संसाधन प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि वर्षों तक तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बार-बार नई परीक्षाओं और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों, भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही देरी और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ नया राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। राजस्थान के कोटा से बुधवार को इस अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं और छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया। देशभर से आए छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज सबसे बड़ा संकट युवाओं के भविष्य से जुड़ा है और सरकार इस चुनौती का समाधान करने में विफल रही है।कोटा लंबे समय से देश की कोचिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है। लाखों छात्र यहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने अभियान की शुरुआत के लिए इसी शहर को चुना। पार्टी का मानना है कि पेपर लीक, भर्ती घोटाले और रोजगार का मुद्दा सीधे तौर पर देश के करोड़ों युवाओं से जुड़ा हुआ है और इसे राजनीतिक विमर्श का प्रमुख विषय बनाया जाना चाहिए।अपने संबोधन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कई भर्ती परीक्षाएं या तो रद्द हुईं या फिर विवादों में घिर गईं, जिससे लाखों युवाओं का समय और संसाधन प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि वर्षों तक तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बार-बार नई परीक्षाओं और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध बनाया जाए और पेपर लीक के मामलों में सख्त जवाबदेही तय हो।कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिए कि आने वाले महीनों में विभिन्न राज्यों में छात्र सम्मेलन और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी इस मुद्दे को केवल चुनावी विषय के बजाय सामाजिक और आर्थिक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे आगामी चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, विशेषकर उन राज्यों में जहां बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं।उधर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा सुधार के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष युवाओं की चिंताओं का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में सामने आए पेपर लीक मामलों ने भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यदि कांग्रेस इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित तरीके से आगे बढ़ाने में सफल रहती है, तो रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दे आने वाले समय में केंद्र की राजनीति के प्रमुख एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।

झारखंड राज्यसभा चुनाव से पहले बढ़ी सियासी चौकसी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव से एक दिन पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। संभावित क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक जोड़तोड़ की आशंकाओं के बीच दलों ने अपने विधायकों के साथ लगातार बैठकें शुरू कर दी हैं। राज्य की राजनीति में चुनावी गणित को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।राज्यसभा चुनाव में संख्या बल भले ही महत्वपूर्ण माना जाता हो, लेकिन कई बार एक-दो वोट भी परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण सभी दल अपने विधायकों की निगरानी और संपर्क बनाए रखने में जुटे हैं। सत्तापक्ष की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर लगातार बैठकें की गईं, जबकि विपक्षी दलों ने भी अपने विधायकों के साथ अलग-अलग रणनीतिक सत्र आयोजित किए। राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक चर्चा संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर हो रही है।राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव परिणाम को लेकर सभी दल आश्वस्त दिखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदरखाने सतर्कता बरती जा रही है। विधायकों को मतदान की प्रक्रिया और दल के निर्देशों की जानकारी दी जा रही है। कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं और किसी प्रकार की टूट की संभावना नहीं है।राज्यसभा चुनाव को केवल संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। चुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश देने का काम करेंगे। यही वजह है कि दलों के शीर्ष नेतृत्व की भी इस चुनाव पर नजर बनी हुई है।विश्लेषकों का मानना है कि यदि मतदान पूरी तरह दलगत आधार पर हुआ तो परिणाम अनुमानित रह सकते हैं, लेकिन किसी भी अप्रत्याशित वोटिंग से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए मतदान तक राज्य की राजनीतिक हलचल बनी रहने की संभावना है।

रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर सरकार का जोर विपक्ष ने रोजगार और निजीकरण पर उठाए सवाल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केंद्र सरकार ने देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए दावा किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भारत अब न केवल अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है।रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में घरेलू निर्माण को बढ़ावा दिया गया है। सरकार का दावा है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ने से उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ है। रक्षा उपकरणों, मिसाइल प्रणालियों, गोला-बारूद और आधुनिक सैन्य तकनीकों के स्वदेशी निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र का मानना है कि इससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की सामरिक शक्ति मजबूत होगी।सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि रक्षा क्षेत्र में बढ़ते निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। कई राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारों और उत्पादन इकाइयों की स्थापना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचा है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक क्षमता का प्रमाण बताया है।हालांकि विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि रक्षा उत्पादन में वृद्धि का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ रोजगार सृजन और उत्पादन के वास्तविक लाभों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। कुछ विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा देकर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका को सीमित कर रही है। विपक्ष का यह भी कहना है कि उत्पादन के आंकड़ों के साथ यह स्पष्ट होना चाहिए कि इससे कितने स्थायी रोजगार उत्पन्न हुए हैं और देश को वास्तविक आर्थिक लाभ कितना मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रक्षा उत्पादन का मुद्दा केवल आर्थिक या सामरिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक ओर सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत की सफलता के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं विपक्ष इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर बहस छेड़ने का प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में संसद और राजनीतिक मंचों पर यह मुद्दा चर्चा का प्रमुख विषय बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास तीनों ही सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं।

NEET UG पुनर्परीक्षा की तारीख तय, 21 जून को परीक्षा

दिव्यांग छात्रों के लिए स्क्राइब पंजीकरण शुरू

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(NTA) ने नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अहम सूचना जारी की है। एनटीए ने पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए स्क्राइब डिटेल्स पोर्टल चालू कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा के दौरान स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से तय समय-सीमा के भीतर अपनी जानकारी जमा कर सकते हैं।

नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि 3 मई को हुई परीक्षा को कुछ अनियमितताओं के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। यह परीक्षा देश और विदेश के कई केंद्रों पर पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। एनटीए ने परीक्षा के दौरान मदद चाहने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यह विशेष पोर्टल शुरू किया है। उम्मीदवारों को अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

पात्र दिव्यांग उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने लॉग इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपनी स्क्राइब डिटेल्स जमा कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स डैशबोर्ड पर जाकर रजिस्टर स्क्राइब डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहां पर स्क्राइब सुविधा का चयन करके जरूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमा की गई जानकारी व्यू एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन में दिखाई देगी।

एनटीए की ओर से जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, स्क्राइब पोर्टल 9 जून, 2026 को खोल दिया गया है। स्क्राइब डिटेल्स जमा करने की आखिरी तारीख 12 जून, 2026 (रात 11 बजकर 50 मिनट) तक तय की गई है। वहीं नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून, 2026 को कराई जाएगी। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी 2026 एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी कर दी है। इससे उम्मीदवार यह चेक कर सकते हैं कि उनका एग्जाम सेंटर किस शहर में है। यह स्लिप एडमिट कार्ड से पहले जारी की गई है ताकि कैंडिडेट्स को अपनी यात्रा और ठहरने की पहले से व्यवस्था करने में मदद मिल सके। उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके ऑफिशियल पोर्टल से इस स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं।

एनटीए ने साफ किया है कि सिटी इंटीमेशन स्लिप केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए है इसे एडमिट कार्ड समझने की भूल न करें। नीट यूजी 2026 दोबारा परीक्षा का एडमिट कार्ड आने वाले दिनों में अलग से जारी किया जाएगा।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 19 जून तक बढ़ी

अगर आप भी इस साल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और किसी वजह से अब तक अपने दस्तावेजों की जांच नहीं करवा पाए थे, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। विभाग ने इसकी अंतिम तिथि, जो पहले 13 जून को खत्म हो गई थी, उसे अब बढ़ाकर 19 जून कर दिया गया है। अब छात्र 19 जून तक अपने संबंधित कॉलेज में जाकर न सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, बल्कि ई-मित्र के जरिए अपनी एडमिशन फीस भी आसानी से जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ने से उन हजारों स्टूडेंट्स को सीधा फायदा होगा जो किसी वजह से अपने जरूरी कागज तैयार नहीं कर पाए थे। तारीखों में बदलाव के बाद अब पहली मेरिट लिस्ट यानी प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची 22 जून को जारी की जाएगी। इसके ठीक बाद 23 जून को छात्रों का सेक्शन निर्धारण और उन्हें विषय अलॉट करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि नया शैक्षणिक सत्र और फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं 1 जुलाई से हर हाल में शुरू कर दी जाएंगी। इस बार कॉलेजों में आवेदन तो खूब आए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वालों की संख्या काफी कम रही है। उदाहरण के तौर पर अलवर के आर्ट्स कॉलेज में 2300 सीटों के लिए 3391 फॉर्म भरे गए, लेकिन सिर्फ 1167 छात्रों ने ही कागज चेक करवाए। वहीं जीडी कॉलेज में बीए के लिए 2421 आवेदन आए, जिनमें से महज 628 स्टूडेंट्स ही वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे। कॉमर्स कॉलेज में भी बीकॉम की 1000 सीटों पर सिर्फ 458 आवेदन मिले और उनमें से भी 242 ने ही वेरिफिकेशन कराया। इसी सुस्ती को देखते हुए विभाग ने तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि कोई पढ़ाई से वंचित न रहे।

गिल-ईशान ने मिलकर किया बड़ा कारनामा

80 से कम गेंदों में शतक लगाने वाली बने पहले भारतीय

महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की नजर लगातार दूसरी जीत पर

पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के साथ आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करने वाली भारतीय टीम बुधवार को अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स से भिड़ेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ 64 रन की प्रभावशाली जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास ऊंचा है और टीम प्रबंधन भी लय को बरकरार रखने पर जोर दे रहा है।भारत ने अपने पहले मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया था। स्मृति मंधाना की अर्धशतकीय पारी और दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान को मुकाबले से बाहर कर दिया था। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई थी। इस जीत ने भारतीय टीम का नेट रन रेट भी मजबूत कर दिया है। नीदरलैंड्स पहली बार महिला टी20 विश्व कप में हिस्सा ले रहा है। हालांकि टीम को अपेक्षाकृत कमजोर माना जा रहा है, लेकिन भारतीय खेमे में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा रही है। कोचिंग स्टाफ का मानना है कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हर मैच महत्वपूर्ण होता है और छोटे अंतर से मिली जीत भी आगे चलकर अंक तालिका को प्रभावित कर सकती है। ग्रुप-1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स शामिल हैं। ऐसे में सेमीफाइनल की दौड़ बेहद प्रतिस्पर्धी मानी जा रही है। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वह कमजोर मानी जा रही टीमों के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करे।

एम्बाप्पे ने विश्व कप में रचा इतिहास, फ्रांस को दिलाई शानदार शुरुआत

फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। ग्रुप चरण के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विश्व कप इतिहास में सबसे तेज गति से गोलों का नया रिकॉर्ड स्थापित किया और अपनी टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। एम्बाप्पे के प्रदर्शन ने न केवल फ्रांस के अभियान को मजबूत शुरुआत दी, बल्कि उन्हें एक बार फिर टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शामिल कर दिया।मैच की शुरुआत से ही फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया। एम्बाप्पे ने अपनी तेज रफ्तार और बेहतरीन फिनिशिंग का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी रक्षा पंक्ति को लगातार दबाव में रखा। उनके गोल ने टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई, जिसके बाद फ्रांस ने मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने उनके प्रदर्शन की जमकर सराहना की।फ्रांसीसी कोच ने मैच के बाद कहा कि एम्बाप्पे केवल गोल स्कोरर ही नहीं बल्कि टीम के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए उनका अनुभव और आत्मविश्वास टीम की बड़ी ताकत है। पिछले विश्व कपों में भी शानदार प्रदर्शन कर चुके एम्बाप्पे अब लगातार रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं।फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एम्बाप्पे इसी लय में बने रहते हैं तो फ्रांस एक बार फिर खिताब का मजबूत दावेदार बन सकता है। विश्व कप के शुरुआती चरण में मिली इस जीत ने टीम का मनोबल बढ़ा दिया है। अब फ्रांस की नजर अगले मुकाबलों में भी जीत का सिलसिला जारी रखने पर होगी।टूर्नामेंट के शुरुआती सप्ताह में मेसी और एम्बाप्पे दोनों के शानदार प्रदर्शन ने फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह बढ़ा दिया है। आने वाले मुकाबलों में इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों पर दुनिया भर के प्रशंसकों की नजरें टिकी रहेंगी।

मेसी ने रचा नया इतिहास, 200वें अंतरराष्ट्रीय मैच में अर्जेंटीना को दिलाई शानदार जीत

फुटबॉल विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। अल्जीरिया के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर उतरते ही मेसी अपने करियर का 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए। इस यादगार मुकाबले में उन्होंने हैट्रिक लगाकर अर्जेंटीना को 3-0 की शानदार जीत दिलाई और अपने करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया।39 वर्षीय मेसी पहले ही विश्व फुटबॉल के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। विश्व कप विजेता, कोपा अमेरिका चैंपियन और कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके मेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर उनका प्रदर्शन आज भी उतना ही प्रभावशाली है। अल्जीरिया के खिलाफ उनकी हैट्रिक ने अर्जेंटीना को टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत दिलाई। फुटबॉल

विशेषज्ञों का मानना है कि मेसी की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और खेल को पढ़ने की क्षमता है। युवा खिलाड़ियों से सजी अर्जेंटीना टीम के लिए उनका नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्व कप में खिताब बचाने उतरी अर्जेंटीना टीम को इस जीत से बड़ा मनोबल मिला है। मेसी की उपलब्धि को लेकर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पर भी उनका नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। अर्जेंटीना के प्रशंसकों को उम्मीद है कि उनका कप्तान इस विश्व कप में भी टीम को खिताब की दौड़ में बनाए रखेगा।विश्व कप के शुरुआती चरण में मिली इस जीत ने अर्जेंटीना को ग्रुप में मजबूत स्थिति दिला दी है। अब टीम की नजर अगले मुकाबलों में भी इसी प्रदर्शन को दोहराने पर होगी।

बॉलीवुड • टीवी • ओटीटी • म्यूजिक • फैशन

खबर 1: बॉलीवुड

‘अल्फा’ ट्रेलर में ऋतिक रोशन की झलक से फैंस उत्साहित

आलिया भट्टूट और शरवरी की स्पाई थ्रिलर में ‘कबीर’ के रोल में दिखे ऋतिक

मुंबई, 16 जून (एजेंसी): यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘अल्फा’ का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हुआ। ट्रेलर में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के साथ ऋतिक रोशन की झलक ने फैंस को चौंका दिया। ऋतिक इस फिल्म में ‘कबीर’ के रोल में नजर आएंगे, जो कि YRF स्पाई यूनिवर्स का अहम किरदार है।

ट्रेलर में शानदार एक्शन, इमोशनल डायलॉग्स और हाई-ऑक्टेन सीन्स देखने को मिले हैं। सोशल मीडिया पर #AlphaTrailer और #Kabir ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस को फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट की कैमिस्ट्री बेहद पसंद आ रही है।

यशराज फिल्मस की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर ‘अल्फा’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। ट्रेलर में ऋतिक रोशन के किरदार ‘कबीर’ की एक छोटी सी झलक ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी है। आलिया भट्टूट और शरवरी वाघ के दमदार एक्शन अवतार को भी दर्शकों ने खूब सराहा है। फिल्म को 25 दिसंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स को और बड़ा करने जा रही है।

खबर 2: ओटीटी

राजकुमार हिरानी करेंगे OTT डेब्यू, ‘प्रीतम एंड पेड़ो’ का ऐलान

अर्शद वारसी और विक्रांत मैसी आएंगे साथ नजर

मुंबई, 16 जून (एजेंसी): ‘3 इडियट्स’ और ‘मुन्नाभाई’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक राजकुमार हिरानी अब ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी नई क्राइम-कॉमेडी सीरीज ‘प्रीतम एंड पेड़ो’ का ऐलान हो गया है, जिसमें अर्शद वारसी और विक्रांत मैसी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

हिरानी ने बताया कि इस सीरीज की कहानी उन्हें मुंबई साइबर सेल से जुड़े एक वास्तविक अनुभव से मिली है। सीरीज में दो अलग-अलग स्वभाव के लोगों की जोड़ी की कहानी दिखाई जाएगी, जो मिलकर साइबर अपराधों की जांच करते हैं। यह सीरीज एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। शूटिंग जल्द शुरू होने की संभावना है।

खबर 3: बॉलीवुड

जैकलीन फर्नांडिस की पहली हॉरर फिल्म, जून अंत में शुरू होगी शूटिंग

अभिनेत्री ने लिया हॉरर जॉनर में एंट्री करने का फैसला

मुंबई, 16 जून (एजेंसी): अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पहली बार हॉरर जॉनर में नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नई हॉरर फिल्म की शूटिंग जून 2026 के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। फिल्म की कहानी एक अनोखे हॉरर कॉन्सेप्ट पर आधारित है।

फिल्म के निर्देशक और अन्य कलाकारों के नाम फिलहाल गोपनीय रखे गए हैं। जैकलीन ने कहा कि यह जॉनर उनके लिए नया और चुनौतीपूर्ण है, और वह दर्शकों को कुछ अलग अनुभव देना चाहती हैं।

KGMU में लागू होगा HIS, मरीज के मोबाइल पर पहुंचेगी हर जानकारी

KGMU में दवा घोटाले के बाद हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम (HIS) लागू करने की तैयारी है। इसके जरिए दवा, जांच और उपकरणों की हर जानकारी मरीज के मोबाइल पर पहुंचेगी। डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

KGMU के यूरोलॉजी विभाग में करोड़ों के दवा घोटाले के बाद डिजिटल निगरानी पर फोकस हैं। जल्द ही हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम (HIS) लागू किया जाएगा। इसके शुरू होने से मरीज के नाम पर होने वाली दवा, जांच, उपकरण और इलाज से जुड़ी हर गतिविधि ऑनलाइन दर्ज होगी। इसकी सूचना सीधे मरीज के मोबाइल तक पहुंचेगी। KGMU में चार हजार बेड हैं। ज्यादातर बेड भरे रहते हैं। प्रतिदिन छह से सात हजार मरीज OPD में आ रहे हैं। मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए आयुष्मान, असाध्य, मुख्यमंत्री, प्रधानामंत्री व पंडित दीन दयाल कैशलेस समेत दूसरी योजनाओं का संचालन हो रहा है। अभी KGMU में इलाज की व्यवस्था ऑनलाइन नहीं है। HIS लागू होने से मरीजों के रिकॉर्ड से लेकर डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन, जांच रिपोर्ट, फार्मेसी और बिलिंग तक पूरी प्रक्रिया एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। इससे न सिर्फ मरीजों को सुविधा मिलेगी, बल्कि अस्पताल प्रशासन को भी हर स्तर पर निगरानी आसान होगी। यूरोलॉजी विभाग से जुड़े कथित दवा घोटाले में आरोप लगे थे कि मृत मरीजों के नाम पर भी दवा और उपकरणों के इंडेंट जारी किए गए। इसी तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए HIS में ऐसा प्रावधान होगा कि मरीज के नाम पर किसी भी दवा या उपकरण की मांग होते ही उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना पहुंच जाएगी। इससे मरीज को पता रहेगा कि उसके नाम पर क्या जारी हुआ है। KGMU में कई बार मरीजों की शिकायत रहती है कि उपलब्ध दवाओं के बावजूद उन्हें बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। HIS में अस्पताल की फार्मेसी का रियल टाइम स्टॉक ऑनलाइन रहेगा। डॉक्टरों को उपलब्ध दवाओं की जानकारी रहेगी। वे उसी आधार पर दवा लिख सकेंगे। इससे मरीजों का खर्च कम होगा। KGMU में फैकल्टी और कर्मचारियों को मिलने वाली निशुल्क दवा सुविधा भी डिजिटल निगरानी के दायरे में आएगी। वर्तमान व्यवस्था में आईडी के आधार पर दवा की मांग होती है। नई व्यवस्था में हर इंडेंट और वितरण की जानकारी संबंधित व्यक्ति तक पहुंचेगी, जिससे किसी और के नाम पर दवा निकालना मुश्किल होगा। अभी HIS सिस्टम पीजीआई व लोहिया संस्थान में लागू है। डॉ. केके सिंह ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने से कई समस्याओं पर रोक लगाई जा सकती है। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। वर्तमान नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर की सीमाओं को देखते हुए बेहतर विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।

लखनऊ में घरेलू कनेक्शन पर चला रहे स्पोर्ट्स सेंटर

लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के लिए अभियान चलाया। शहर के विभिन्न जोनों में सघन चेकिंग अभियान चला कर कार्रवाई की। इस दौरान कार्रवाई में कुल 11 उपभोक्ता मीटर बाईपास कर बिजली चोरी करते पकड़े गए, जिनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं, एक उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन से युवा स्पोर्ट्स सेंटर चलाते पकड़ा गया। अमौसी जोन में अधिशासी अभियंता, रेड असेसमेंट एंड कलेक्शन, अमौसी क्षेत्र के निर्देशन में चलाए गए अभियान में 57 संयोजनों की जांच हुई। जांच में 5 उपभोक्ता मीटर बाईपास कर चोरी करते पाए गए। पकड़े गए उपभोक्ताओं में ललित वर्मा, रामचंद्र, रामकिशुन श्रीवास्तव, श्रवण और राजू लोधी शामिल हैं। इनका विद्युत भार 2.239 किलोवाट से 8.612 किलोवाट तक पाया गया। मध्य क्षेत्र के राजाजीपुरम में चलाए गए अभियान में दो उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए। मयंक सक्सेना और प्रभा वर्मा के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जानकीपुरम जोन 33/11 केवी उपकेंद्र दाऊद नगर के अंतर्गत मामा चौराहा 60 फीट रोड पर चलाए गए अभियान में 34 परिसरों की जांच की गई। यहां जगत नारायण, घरेलू कनेक्शन से अतिरिक्त केबल जोड़कर 7.5 किलोवाट का युवा स्पोर्ट्स सेंटर अवैध रूप से चलाते पाए गए। इसके अलावा गोमती नगर जोन में उपकेंद्र छोटा भरवारा, लौलाई और विराज खंड-2 में 26 परिसरों की चेकिंग में 3 उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपभोग करते मिले। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग की ओर से सभी उपभोक्ताओं को नियमों की जानकारी लगातार दी जा रही है। उल्लंघन करने वाले किसी भी उपभोक्ता को छोड़ा नहीं जाएगा।

आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली, फिर भी गूंजा गिल-ईशान के शतकों का शोर

इकाना स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे इंटरनेशनल खेला गया। उमस भरी गर्मी के चलते आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली रहा। इकाना स्टेडियम में 50 हजार सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 14 हजार दर्शक ही मैच देखने पहुंचे थे। मैच के दौरान रोहित और विराट की जर्सी का काफी क्रेज देखने को मिला। स्टेडियम के बाहर 200 से 300 रुपए तक में ये जर्सियां मिल रही थी। मैच देखने सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी के सुपरफैन पहुंचे थे। रोहित शर्मा के पर्सनल नेट बॉलर रहे शिवपाल सिंह देवड़ा भी पुणे से मैच देखने आए थे। लखनऊ में मैच शुरू होने के दौरान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके बाद दोपहर बाद तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। उमस भरी गर्मी के चलते फैन पसीने पसीने हैं और छाव खोजते नजर आए। तेज धूप से हवाओं के गर्म थपेड़े महसूस भी किए गए। इस दौरान कई फैंस गमछा ओढ़कर स्टेडियम में मैच देखते नजर आए। ईशान किशन और शुभमन गिल ने शतक लगाया। किशन ने 71 गेंदों में शतक पूरा किया। गिल इकाना स्टेडियम में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। वहीं, इकाना में पहली बार वनडे में 402 रन का स्कोर बना है। इकाना में पहली बार हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला।

करोड़ों के कथित घोटाले की जांच में अयोध्या पहुंची सीबीआई, सुबह-सुबह छापेमारी

अयोध्या अमेठी के वित्त एवं लेखा विभाग में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बुधवार सुबह अयोध्या में छापेमारी की। सीबीआई की टीम सुबह करीब 5:30 बजे कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकली पुलिस चौकी के निकट स्थित एक मकान पर पहुंची और जांच शुरू की। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने पवन कुमार मालवीय के आवास पर दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच की। टीम ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र कीं और मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की। जांच के दौरान स्थानीय पुलिस को भी आवश्यक सहयोग के लिए अलर्ट रखा गया था। बताया जा रहा है कि अमेठी के वित्त एवं लेखा विभाग में हुए करोड़ों रुपए के कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अदालत के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है। इसी क्रम में एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई की। अयोध्या के अलावा अमेठी, लखनऊ, प्रतापगढ़ और कुशीनगर में भी सीबीआई की टीमों ने संबंधित लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई सीबीआई की डीआईजी शिवानी तिवारी के निर्देशन में की गई। अयोध्या में करीब ढाई घंटे तक चली जांच के बाद सुबह लगभग 8 बजे टीम वहां से रवाना हो गई। हालांकि, सीबीआई अधिकारियों ने जांच से जुड़े किसी भी बिंदु पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। घोटाले की जांच में सीबीआई लगातार दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल में लगी हुई है।

लखनऊ के शारदा सहायक नहर में मिला नवजात का शव

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह शारदा सहायक नहर में एक नवजात शिशु का शव मिला है। केटल घाट के पास नहर में शव को बहता देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह कुछ लोगों की नजर नहर में बह रहे एक नवजात के शव पर पड़ी। शुरुआत में उन्हें स्थिति का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चला कि वह नवजात शिशु का शव है। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और नवजात की पहचान तथा शव के नहर में पहुंचने की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही गोमती, घटते जलस्तर से नदी में दिखने लगे टीले

लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। जिसके कारण से कई जगह गोमती सूखी हुई नजर आ रही है। नदी के कुछ हिस्सों पर टीले नजर आ रहे हैं। इन दिनों ये नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ जहां शहर के गंदे नाले सीधे इस पवित्र नदी में गिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्यों और अन्य वजहों से कहीं-कहीं इसकी प्राकृतिक धारा को बांधकर रोक दिया गया है। गोमती बैराज के गेटों की मरम्मत की वजह से बैराज का पानी रोके जाने से पहले नदी में जो गहराई दिखती थी, अब वह काफी कम हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के मुख्य हिस्सों से जहां घूमती नदी गुजर रही है वहां बुरा हाल है। कुड़िया घाट , मेहंदी घाट , इसके अलावा रिवर फ्रंट इन सब जगह पर गोमती का पानी बिल्कुल दूषित हो चुका है। कूड़े का ढेर, गंदगी, बदबूदार पानी और सुखी मिट्टी है गोमती की नई पहचान बन गई है। लोग कहते हैं कि पहले इसका पानी पीकर लोग अपनी प्यास बुझाते थे। गंदगी की वजह से अब इस ओर देखा तक नहीं जा रहा है। रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग वॉक करने आए रमेश चंद्र ने कहा कि अब यह नदी नहीं रही नाल हो गई है। सीवर का पानी इतना ज्यादा गिर रहा है कि गोमती का अपना फ्लू खत्म हो गया है। मछलियों समेत तमाम जीव जंतुओं की मौत हो रही है। इसकी

सफाई के लिए सरकार को आगे आना चाहिए ताकि इसका कल्याण हो सके। अजय ने बताया कि पहले इतनी स्वच्छता होती थी कि लोग इसका डायरेक्ट पानी पीते थे। 35 साल पहले जब यहां बाढ़ आई थी तो हम लोग गोमती नदी का अद्भुत दृश्य देखने के लिए आते थे। वॉटर लेवल इतना ऊंचा हो जाता था कि देखने लायक होता था। अब तो गोमती में बिल्कुल पानी बचा ही नहीं यह देखकर बहुत अफसोस होता है। जगह-जगह टीले बन गए हैं। कीचड़ नजर आता है। गोमती ऐसे तो नहीं रहती थी। किसी भी सरकार में इस पर ध्यान नहीं दिया। जानकारी मिली है कि स्टीमर चलने वाला है अब यह नाला हो चुका है तो क्या नाले में स्टीमर चलेगा।

उन्नाव को 358 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात,

मुख्यमंत्री योगी ने किया लोकार्पण व शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उन्नाव जनपद को विकास की नई सौगात देते हुए 358 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 69 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। बिछिया ब्लॉक के डीह स्थित भौनीखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 139.86 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुई 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 218.27 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 52 नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर जिले के विकास को नई गति देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री निर्धारित समय पर सुबह लगभग साढ़े दस बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने व्यापक तैयारियां की थीं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। हेलीपैड, वीआईपी मार्ग, पार्किंग, बैरिकेडिंग और जनसभा स्थल की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार निगरानी रखी। जिलाधिकारी समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम से पूर्व कई दौर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क, आधुनिक सुविधाएं और मजबूत आधारभूत ढांचा किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला होते हैं। उन्नाव में शुरू की गई नई परियोजनाएं क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कार्यक्रम के दौरान सदर विधानसभा क्षेत्र में 127.04 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुई पांच प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें दोस्तीनगर बाईपास का निर्माण, मंधना-गंगाबैराज-शुक्लागंज-पुरवा-मोहनलालगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, पंडितखेड़ा से आंट संपर्क मार्ग का निर्माण, राज्य कर विभाग के मंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण तथा बरबट नहर पुल पर क्षतिग्रस्त आर्च सेतु का पुनर्निर्माण शामिल है। इसके अलावा भगवंतनगर विधानसभा क्षेत्र में 1.38 करोड़ रुपये की लागत से पनहन से पुरन्दरपुर मार्ग तथा नौगंवा से सलारपुर मार्ग का लोकार्पण किया गया। वहीं पुरवा विधानसभा क्षेत्र में 11.44 करोड़ रुपये लागत वाली 10 विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित की गईं।मुख्यमंत्री ने 52 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार होगा और जिले में विकास की रफ्तार और तेज होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही।

11 घंटे बाधित रही सैकड़ों गांवों की बिजली आपूर्ति

उन्नाव के सफीपुर स्थित मियागंज ब्लॉक क्षेत्र में बुधवार सुबह आठ बजे 33 केवी का एक विद्युत पोल टूट गया। इससे 33 केवी विद्युत लाइन में खराबी आ गई और सैकड़ों गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। यह व्यवधान करीब 11 घंटे तक रहा। विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए एसडीओ धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। टीम ने टूटे हुए विद्युत पोल की मरम्मत की और फाल्ट को ठीक किया। शाम करीब सात बजे तक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गई। इसी बीच, कादिरपुर गांव में रात के समय ट्रांसफार्मर के पास एक विद्युत तार टूट गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कनौजिया ने इसकी सूचना एसडीओ धर्मेंद्र कुमार को दी। सूचना मिलते ही लाइनमैन सीताराम को टीम के साथ मौके पर भेजा गया है। एसडीओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कादिरपुर में फाल्ट को ठीक करने का काम जारी है और जल्द ही वहां भी बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

उन्नाव क्रिकेट स्टेडियम में अनियमितता के आरोपों को यूपीसीए ने किया खारिज

उन्नाव के मुर्तजानगर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम में तीन करोड़ रुपये के कथित वित्तीय अनियमितता के आरोपों को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने खारिज कर दिया है। यूपीसीए के पदाधिकारियों ने इन आरोपों को निराधार बताया है। यह मामला तब सामने आया जब सोमवार को वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और पूर्व रणजी खिलाड़ी मोहसिन रजा ने स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वर्ष 2011 में स्टेडियम और क्रिकेट एकेडमी के निर्माण के लिए 21 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन मौके पर कोई बड़ा निर्माण कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। रजा ने यह भी दावा किया कि यूपीसीए की बैलेंसशीट में पिछले पांच वर्षों से स्टेडियम पर तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दर्ज है, जबकि धरातल पर कोई कार्य नजर नहीं आ रहा। उन्होंने इसे वित्तीय अनियमितता बताते हुए जांच की मांग की थी। इन आरोपों के जवाब में, यूपीसीए के पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने मुर्तजानगर स्थित स्टेडियम की जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यूपीसीए ने स्टेडियम निर्माण के लिए लगभग 13 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। गुप्ता ने स्पष्ट किया कि बीसीसीआई की ओर से केवल जमीन खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। अन्य निर्माण कार्यों के लिए कोई बजट नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मौके पर जो भी निर्माण कार्य दिख रहा है, वह जमीन बेचने वाले पक्ष द्वारा कराया गया है। इस प्रकार, स्टेडियम निर्माण में धन के दुरुपयोग या अनियमितता के आरोप पूरी तरह गलत हैं। यूपीसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व सचिव, तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन अरविंद कमल ने भी इन आरोपों को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि यूपीसीए की ओर से न तो मैदान का समतलीकरण कराया गया है और न ही पिच निर्माण का कोई कार्य कराया गया है। उन्होंने कहा कि लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में यूपीसीए वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वाराणसी परियोजना के बाद ही गाजियाबाद और उन्नाव में खरीदी गई जमीनों पर आगे की योजना बनाई जाएगी। इस दौरान जिला क्रिकेट एसोसिएशन के महामंत्री पीके मिश्रा भी मौजूद रहे। यूपीसीए पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था की सभी गतिविधियां नियमों के अनुसार संचालित हो रही हैं और स्टेडियम निर्माण को लेकर लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है।

उन्नाव में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां प्रदर्शित

उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित हुआ। इसमें सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान परिषद सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास, विश्वास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाओं को लागू किया है, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता, बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार, पुरवा विधायक अनिल सिंह, भगवंतनगर विधायक आशुतोष शुक्ला और सफीपुर विधायक बंबा लाल दिवाकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को दर्शाया गया। इनमें गरीब कल्याण, किसान हित, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आधारभूत विकास से जुड़े कार्य शामिल थे। कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने प्रदर्शनी के माध्यम से इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उपस्थित नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के तेजी से विकास की ओर अग्रसर होने की बात कही। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। इस अवसर पर आनंद अवस्थी, अवनीश गुप्ता, नीरज शुक्ला सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना था।

घर पर रहकर की तैयारी, भारतीय वायु सेना में चयनित हुई वैष्णवी

जिले के भगवंत नगर क्षेत्र स्थित मरोई गांव की बेटी वैष्णवी भट्ट ने भारतीय वायु सेना में चयनित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 22वीं रैंक प्राप्त कर यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उनकी सफलता से गांव और आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल है तथा लोग उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं। वैष्णवी की इस उपलब्धि पर बुधवार को जिला सहकारी बैंक उन्नाव के अध्यक्ष अरूण सिंह और आशुतोष त्रिपाठी 'विजय' उनके आवास पहुंचे। उन्होंने वैष्णवी को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी उनका उत्साहवर्धन किया और देश सेवा के इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए बधाई दी।जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरूण सिंह ने कहा कि वैष्णवी भट्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या महंगे संसाधनों की मोहताज नहीं होती। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर इतनी उत्कृष्ट रैंक हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उनकी सफलता क्षेत्र की अन्य बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि वैष्णवी भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगी।वैष्णवी भट्ट की सफलता की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने किसी बड़े शहर में जाकर कोचिंग नहीं की। उन्होंने घर पर रहकर ही डिफेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन किया और लगातार मेहनत के बल पर मात्र 13 महीनों की तैयारी में भारतीय वायु सेना में चयन सुनिश्चित किया। उनकी इस उपलब्धि ने यह संदेश दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है।

भैंस बांधने को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर मारपीट

उन्नाव के मौरावां थाना क्षेत्र के पारा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। भैंस बांधने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया, वहीं महिलाओं ने कुल्हाड़ी से भी वार करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और घायल हुए लोगों को मौरावां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उपचार के लिए भर्ती कराया। घायल अफसाना ने बताया कि विवाद भैंस बांधने को लेकर शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। विरोध करने पर मामला और बढ़ गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी हमला किया। अफसाना के अनुसार, मारपीट के दौरान महिलाओं ने कुल्हाड़ी से भी वार किए। पीड़ित पक्ष ने गांव के चार लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसके कारण भैंस बांधने जैसी मामूली बात ने बड़ा रूप ले लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

राम मंदिर को 11 माह में ₹82.78 करोड़ का चढ़ावा

ब्याज से हुई ₹138 करोड़ की अतिरिक्त आय

उल्लेखनीय है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 15 सदस्यीय संस्था है, जिसे राम मंदिर के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं, जबकि चंपत राय महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्षता पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह नृपेंद्र मिश्र कर रहे हैं।

राम मंदिर के चंदे को लेकर हाल के दिनों में चल रही चर्चाओं और आरोप-प्रत्यारोपों के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी आय और व्यय का विस्तृत वित्तीय ब्यौरा सार्वजनिक किया है। ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक की 11 माह की अवधि में राम मंदिर को श्रद्धालुओं से कुल ₹82.78 करोड़ का चढ़ावा प्राप्त हुआ। यह विवरण 21 मार्च को अयोध्या में आयोजित ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया।ट्रस्ट द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर में स्थापित दानपात्रों के माध्यम से सबसे अधिक ₹54.79 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा मंदिर में संचालित नकद काउंटरों से ₹18.88 करोड़ का योगदान मिला। ऑनलाइन माध्यम से श्रद्धालुओं ने ₹28.33 करोड़ का दान दिया, जबकि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत विदेशों से ₹0.78 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।ट्रस्ट ने बताया कि चढ़ावे के अतिरिक्त उसे बैंक जमा पर ब्याज के रूप में भी उल्लेखनीय आय हुई है। अयोध्या स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में जमा राशि पर ट्रस्ट को इसी अवधि में ₹138.03 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ। इस प्रकार चढ़ावे और ब्याज को मिलाकर 11 माह के दौरान ट्रस्ट की कुल आय ₹220.81 करोड़ रही।बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राम मंदिर निर्माण और उससे संबंधित अन्य कार्यों पर व्यय किए जाने के बाद भी ट्रस्ट के पास लगभग ₹2,100 करोड़ की राशि शेष है। इस धनराशि को विभिन्न बैंकों में सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में निवेश किया गया है, जिससे ट्रस्ट को नियमित रूप से ब्याज आय प्राप्त हो रही है।वित्तीय विवरण के अनुसार, उक्त अवधि में ट्रस्ट ने कुल ₹364.44 करोड़ का व्यय किया। यह खर्च मंदिर निर्माण, आधारभूत संरचना विकास, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा अन्य संबंधित परियोजनाओं पर किया गया।उल्लेखनीय है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 15 सदस्यीय संस्था है, जिसे राम मंदिर के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं, जबकि चंपत राय महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्षता पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह नृपेंद्र मिश्र कर रहे हैं।गौरतलब है कि नवंबर 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। तभी से यह स्वायत्त संस्था मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन का कार्य संभाल रही है।

केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और भाजपा लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर से जुड़े विवाद, ब्राह्मण सम्मेलन की राजनीति और छत्तीसगढ़ सरकार के हालिया फैसले पर भी खुलकर अपनी राय रखी। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का राजनीतिक जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में कुछ राजनीतिक दलों की स्थिति कमजोर हुई है, उसी तरह 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी बुरा हाल होगा। मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव की साइकिल अब सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचेगी और केवल सैफई तक सीमित रह जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई सांसद और नेता वर्तमान नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं। मौर्य ने कहा कि सपा के लगभग 25 से 26 सांसद टूटने की स्थिति में हैं, लेकिन भाजपा किसी प्रकार की तोड़फोड़ की राजनीति नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव नजदीक आते-आते सपा के अंदरूनी मतभेद और अधिक खुलकर सामने आएंगे। कानपुर में दिया गया उनका यह बयान आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है। खासकर सपा को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी और सांसदों के टूटने संबंधी दावे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

हाईवे पर मौजूद शंग्रीला फैमिली रेस्टोरेंट की पार्किंग से चोरी होने पर इलाके में हड़कंप

उत्तर प्रदेश में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बाराबंरी से बड़ी चोरी की खबर सामने आई है। बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ-अयोध्या हाईवे किनारे से शातिर चोरों ने 1 करोड़ के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ये घटना हाईवे किनारे स्थित नामचीन शंग्रीला फैमिली रेस्टोरेंट की पार्किंग से हुई। 16 जून की रात ये घटना घटी। दरअसल, एक परिवार बहराइच में एक शादी समारोह से शामिल होकर लखनऊ लौट रहा था। इस दौरान परिवार हाईवे किनारे स्थित मशहूर शंग्रीला फैमिली रेस्टोरेंट में कुछ देर के लिए रुका। इस बीच शातिर चोरों ने पार्किंग में खड़ी कार का शीशा तोड़कर करीब 1 करोड़ रुपये के जेवरात और 30 हजार रुपये की नगदी उड़ा ली। हैरान करने वाली बात ये है कि जब ये घटना घटी, तब रेस्टोरेंट में भारी भीड़ थी। यही वजह है कि इस चोरी की बड़ी वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। चोरी की ये वारदात इकराम खान के साथ हुई, जो बाराबंकी के बदोसराय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिलहाल लखनऊ में रहते हैं। इकराम खान 16 जून की रात बहराइच में सपरिवार एक शादी में शरीक हुए। इसके बाद वापस लखनऊ लौटते हुए परिवार करीब रात 9 बजे हाईवे किनारे मौजूद शंग्रीला रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए रुका। कार को रेस्टोरेंट पार्किंग में खड़ा करके पूरा परिवार खाना खाने के लिए अंदर चला गया। करीब 1 घंटे बाद जब वे वापस लौटे, तो कार की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और करोड़ों के गहनों व नगदी से भरा बैग नदारद था। जिस रेस्टोरेंट की पार्किंग से गहने चोरी हुए, वो अपने वेज-नॉनवेज जायके के लिए इलाके में मशहूर है। शाम होते ही यहां ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है और गाड़ियों की कतार लग जाती है। इसके बावजूद,भारी भीड़ के बीच चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे रेस्टोरेंट की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और पीड़ित परिवार को आगे की कार्रवाई के लिए अगले दिन बुधवार यानी 17 जून की सुबह बुलाया। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी है और रेस्टोरेंट के CCTV की फुटेज खंगाल रही है।

ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत

मुरादाबाद में 24वीं वाहिनी प्रांतीय सशस्त्र आरक्षी दल (PAC) परिसर स्थित कैंटीन में बुधवार दोपहर को अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह LPG गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट बताया जा रहा है। सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग तेजी से पूरे कैंटीन क्षेत्र में फैल गई और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग तुरंत हरकत में आया और मुरादाबाद फायर स्टेशन से दो फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए। फायर टीम ने पहुंचते ही स्थिति का जायजा लिया और देखा कि कैंटीन परिसर में आग तेजी से फैल रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में भी खतरा बढ़ गया था। अग्निशमन कर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए मोटर फायर इंजन की मदद से पाइपलाइन बिछाई और पानी की तेज बौछारों के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। लगातार प्रयासों के बाद धीरे-धीरे आग की लपटों को नियंत्रित किया गया और स्थिति को गंभीर होने से बचा लिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडेय और अग्निशमन अधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने लगातार मेहनत करते हुए आग बुझाने का अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया और कैंटीन परिसर को सुरक्षित किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गैस सिलेंडर फटने के कारण आग अचानक विकराल हो गई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। समय रहते फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।